चाहता हूं कि बावजूद इनके पकड़ जाने के दिल्ली में जो साजिश हो रही है, दिल्ली जो इनके निशाने पर है इसके लिए सतर्कता बनाए रखें और आतंकवादियों, देश के दुश्मनों के जहां संभावित अड्डे हैं, साथी, सहयोगी और हितैषी हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही पाकिस्तानी दूतावास और अनेक दूतावासों पर भी नजर रखने की जरूरत है। गृह मंत्री जी अपनी प्रो-एक्टिव नीति की आलोचना की परवाह किए बिना उसे जारी रखें। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टाडा के खत्म होने के बाद देश के दुश्मनों की कार्यवाहियों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए शीघ्र ही टाडा का स्थान लेने वाला एक उपयोगी कानून बनाया जाए। मुंबई में जो सैकड़ों लोगों की हत्या हुई थी, उन अपराधियों में से किसी को अभी तक सजा नहीं मिली। लेकिन ठीक उसी समय जब न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिस आदमी ने वहां पर हत्यायें की थी या बम डाला था, उस षड्यंत्रकारी पाकिस्तानी नागरिक अहमद युसुफ को अमरीकी न्यायाधीश के बिना पैरोल के 240 साल की सख्त कैद की सजा और साढ़े 45 लाख डालर का जुर्माना किया है और यह कहा कि उसे काल कोटरी में रखा जाए, जहां उसे कोई न मिल सके। न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि यह केवल आतंकवाद या उग्रवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि You are buchers, liars and hyprocrites. महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन हत्यारों की भीषण अपराधों और मानवता के नाम पर कलंकों की शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाए जाए और जो पी०वी०आई०पी० को मारने और दिल्ली तथा पंजाब में फिर से आतंकवाद स्थापित करने की जो साजिश है इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, may I suggest one thing? Sir, the hon. Member has made a vital statement. He might be having his own access to the vital information.

MR. CHAIRMAN: He has collected it from various newspapers.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I have collected it by reading all the newspapers.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I agree with him on this point. What I am suggesting is that the House has a right to know from the Government to what extent the report that has been tabled before the House is correct and what the Government proposes to do with regard to the security environment. (*Interruptions*). That is what I am saying. It is not a question of the VVIPs only. It is a question of the general security environment of the country affecting the general interest of the common people also.

Tabling of Final Report of Jain Commission along with ATR.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश का पता लगाने के लिए 13 अगस्त, 1991 को जैन कमीशन का गठन किया गया था। इस जैन कमीशन ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 17 वैल्यूम में 26 अगस्त, 1997 को प्रस्तुत की थी। गृह मंत्रालय ने इसको एक्जामिन किया था और उसके बाद इंटर डिपार्टमेंट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने यह कहा कि उन्हें जैन कमीशन के समक्ष जो गवाह प्रस्तुत हुए थे, उसके पूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाए हैं और जो वांछित जानकारी है व पूरी उपलब्ध नहीं हो पायी है। साथ ही, अंतरिम रिपोर्ट जो 28.8.97 को प्रस्तुत की गई थी, उस पर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, पेज 8 से पेज 85 तक, तो दरअसल उसमें सरकार की तरफ से जो एक्शन लेने की बात थी, वह पर्याप्त नहीं था। बल्कि यह कहा गया था कि यह एक्शन टेकन रिपोर्ट न होकर नो-एक्शन टेकन रिपोर्ट है। यह भी कहा गया था कि बाद में जब कमीशन की फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो उसके बाद सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट की वांछित जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे प्रस्तुत करेगी और जो दोषी उसमें बताए जाएं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अब जैन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट 8 मार्च, 1998 को प्रस्तुत कर दी है। जिसमें ऐसा बताया गया है कि सभी वांछित जानकारी का ब्यौरा, जो जो इनफॉरमेशन चाही गई थी, जिन लोगों के कथन हुए थे, उसका विस्तार से उल्लेख है। मान्यवर, आए दिन विभिन्न समाचार-पत्रों में यह समाचार छपते हैं, इस फाइनल रिपोर्ट के हवाले से, मेरे पास पेपर हैं, कहीं छपा है चन्द्रास्वामी के सी०आई०ए० से संबंध और मोसाद की भूमिका की जांच की सिफारिश की गई है, कहीं कहा गया है कि 21 संदेहास्पद लोग जिनको जैन कमीशन ने शार्ट लिस्ट किया है, उनकी जांच का उल्लेख इसमें किया गया है। यह मामला जब तक पूरा उजागर नहीं होता, जब तक इस जैन कमीशन की

फाइनल रिपोर्ट इस सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं की जाती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि यह मामला कोई आसान नहीं है बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है और पूर्व में जब जब इस मामले पर कोई डिसकशन हुआ है तो सारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने सारी राजनीतिक सीमाओं को लांघ कर यह मांग की है कि जो भी राजीव गांधी की हत्या में शुमार लोग रहे हों या उनकी हत्या की साजिश में शुमार रहे हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें कठघरे में खड़ा करना चाहिये। इसलिए मेरा विश्वास है कि जैन कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट है, वह सदन के पटल पर अविलम्ब मय एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस पर डिसकशन हो। मान्यवर, एक दिक्कत आती थी जिसका उल्लेख हमेशा जो जो सरकार रही है, वह किया करती थी, वह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमेशा यह कहा जाता था कि सी०बी०आई० के द्वारा पूनामल्ली कोर्ट में जो जांच चल रही है, उसमें कुछ डॉकुमेंट सबमिटेड हैं, उन डॉकुमेंट्स की वजह से जो कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है। महोदय, अब पूनामल्ली कोर्ट में सी०बी०आई० द्वारा जांच कर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है बल्कि हम जब आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि जिन 26 लोगों को दोषी करार दिया गया था उनको बचाने के लिए बार एसोसियेशन के जो विदेश के लोग हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग हैं, उन लोगों ने लगभग 20 लाख रुपये उन को बचाने के लिए इकट्ठे किये हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी आगे की पैरवी के लिए जा रहे हैं। समाचार पत्रों में यह छपा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को बचाने के लिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फोरेन की बार एसोसियेशन के लोग जो सक्रिय हो रहे हैं उनके साथ-साथ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का हाथ है तो इस सरकार में बैठे हुए एक मंत्री का भी हाथ है। इससे कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग राजीव गांधी की हत्या में शुमार रहे हैं, साजिश में शुमार रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। यह तभी संभव है जब जैन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी जाएगी मय एक्शन टेकन रिपोर्ट और उस पर डिसकशन होगा। धन्यवाद।

श्री गुलाम नबी आज़ाद (जम्मू और कश्मीर): सभापति महोदय, मेरे साथी सुरेश पचौरी जी ने बताया कि 1991 में दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें एक ऐसे लीडर की हत्या की गई जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व को कई मामले ठीक करने के लिए मदद दे सकता था, सहायता दे सकता था उनकी लीडरशिप से हिन्दुस्तान ही नहीं पूरा विश्व वंचित रहा। जैन कमीशन ने पिछले साल रिपोर्ट दी और वह रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं थी, इंटेरिम रिपोर्ट थी और उस इंटेरिम रिपोर्ट से मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में एक नया बदलाव आया। इलेक्शन हुए और एक नया राजनीतिक मोड़ भी आया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कितनी जरूरी थी वह रिपोर्ट जिससे सरकारें बदल सकती थीं, बन सकती थीं लेकिन उस वक्त भी तमाम राजनीतिक दलों की यही मांग थी कि इस विवाद को ज्यादा आगे न बढ़ाया जाए, इस पर ज्यादा चर्चा न की जाए, जब तक फाइनल रिपोर्ट न आ जाए। आज मार्च से फाइनल रिपोर्ट आई हुई है। पिछले 15 दिनों से इंडियन एक्सप्रेस में, मैं उसको दोषी नहीं ठहराता हूं यह तो इनकी काबलियत है कि अपने ऐवेन्यूज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी तीसरी दफा आया है। 10-15 दिन में तीसरी दफा रिपोर्ट आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले वक्त में पार्लियामेंट से अखबारों को खबरें मिलती थीं, आज अखबारों से पार्लियामेंट को खबरें मिलती हैं। पहले पार्लियामेंट को अखबार वाले कोट करते थे। आज हम अखबार वालों को पार्लियामेंट में कोट करते हैं। आज जो इन्फारमेशन या डिस-इन्फारमेशन — हमें यह मालूम नहीं है कि इनफारमेशन है या डिस-इन्फारमेशन क्योंकि अखबार के द्वारा जो आई है जब तक पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर या कोई दूसरे मिनिस्टर इस रिपोर्ट को नहीं रखेंगे तब तक यह हमारे लिए वाजिब नहीं है किसी कंक्लूजन पर आना कि यह ठीक है या नहीं है।

बहुत सारी बातों का उल्लेख मेरे साथी ने किया जो हिंदी और इंग्लिश के अखबारों में आया है। हम कहना चाहते हैं कि कभी अमुक एक इन्सान के बारे में बताया जाता है कि उसका इन्वाल्वमेंट है, कभी दूसरे के बारे में बताया जाता है कि फलां के लिंक हैं चाहे बाहर से लिंक है या अंदर से लिंक है। मैं समझता हूं कि यह सदन और देश के करोड़ों लोग यह जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। फाइनल रिपोर्ट कई महीनों से पड़ी है। फिर इसकी जिम्मेवारी किस पर है? मुझे अफसोस होता है कि पार्लियामेंट में रिपोर्ट नहीं रखी जा रही है बल्कि अखबारों को सिलेक्टिवली लीक की जा रही है और अगर लीक की जा रही है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। मेरे ख्याल में माननीय चेयरमैन

साहब इसके लिए किसी न किसी आदमी को सरकार में जिम्मेवारी को लेना चाहिए कि पार्लियामेंट को यह इत्तिला नहीं दी जाती है और अखबारों को यह लीक की जा रही है।

हमारा यह आपसे आग्रह है माननीय चेयरमैन साहब की आम स्पेशल मेंशन की तरह — मैं यह नहीं कहता कि आम स्पेशल मेंशन या दूसरे स्पेशल मेंशन जरूरी नहीं होते हैं, दूसरे स्पेशल मेंशन भी बहुत जरूरी होते हैं लेकिन आम जो ऐसा होता है आमदन्द, शिस्तन्द, बरखास्तन्द" — वैसा वाला काम नहीं होना चाहिए कि आए, बैठे, सुना और चले गए। हमारे दो साथी मंत्री यहां बैठे हैं मैं इनसे निवेदन करूंगा कि यह बात माननीय गृह मंत्री महोदय की नोटिस में लाएं कि इस चीज पर यहां स्टेटमेंट होना चाहिए और न सिर्फ स्टेटमेंट ही बल्कि एक्शन टेकन रिपोर्ट इस सदन में सदन के पटल पर रखनी चाहिए और रिपोर्ट ही नहीं रखनी चाहिए उस पर पूरी चर्चा भी होनी चाहिए। सभी पार्टियों के सदस्य जो हमारे सदस्यगण हैं उनको मौका देना चाहिए उस पर चर्चा करने के लिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन एजेंसिज थीं, कौन लोग राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेवार थे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I carefully listened to what my colleagues have stated here. We have read this report in the newspaper and some serious allegations have been made in that report. He has been remembered for his contributions not only as the leader of the Congress Party but also as the Prime Minister, as the leader of the nation. The most important point which I want to raise is that the hands of certain forces from inside and outside are behind it. I am forced to believe it today because a news item appeaed in the Press that through the legal channel more than Rs 20 lakhs had already come to defend the accused people who had been convicted by a Madras court. The hint is that through the illegal channel how much would have come. Some of the observations in the report are being strengthened by the actions of a group of people who try to make the accused as heroes. This is a matter of concern not only to the Congress Party but also to the nation because a former Prime Minister was assassinated. Three months have passed. The Government knows the sensitivity of the report. But the final report was not placed before the Parliament. Earlier when the interim report came the argument put forward was, "let the full report come, the Government will come forward". There is a change of guard. I agree. This Government has got three months' time at its disposal. It should have easily gone through the report and placed before this House an action taken report. Unfortunately, we, Members of Parliament, as Mr. Azad has rightly pointed out, have to come to know these things through the newspapers. It matters us more. Moreover, I have to make a request to the Prime Minister that he must have some kind of control over his Ministers because the name of a Minister has been associated with the collection of funds to defend the accused who have been convicted. The name of one of the Ministers has been associated with it. That Minister, who is associated with it, defied the law in Delhi and courted arrest because he stated, "it is my duty to defend"

Moreover, our judiciary is being insulted by the Human Rights Commission and the Amnesty International. Do they think that the Indian judiciary is partial? What is the need of an observer for this kind of a trial which is going on? Some people here have demanded that observers must come from the Hague and Geneva. We might have criticised our judiciary. But we are proud of our judiciary. They are not at all partial. In certain cases we know how they have taken decisions. Sir, some people are demanding that observers should come and sit in the Supreme Court to watch the trial. It is an insult to the Indian judicial system. The Government of India and the Indian judiciary must take a position. They should say, "We know how we have to decide this question". I would like to have a response from the Minister of Parliamentary Affairs. When are they going to place it before the House? We

want an assurance from the Government. I would like to know whether they would place it during the current Session itself. I demand of the Prime Minister and the Home Minister that they must come before the House with an Action Taken Report during the current Session itself. We suspect that one of the Ministers of his Cabinet is involved in fund collection. I don't know whether he has denied it or not. If you want me to name him, I can name him. I don't want to name him. There are enough reasons to believe that he is involved in fund collection. If he is not involved, we are very happy. It is for the Prime Minister to see whether one of the Ministers of his Cabinet is involved in fund collection. If it is so, he should reprimand him. Sir, he must come out with an Action Taken Report to protect the interests of the whole nation and the judiciary and to make us feel that the Government is going towards the right direction. Thank you.

श्री जितेन्द्र प्रसाद (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, जब से श्री राजीव गांधी की हत्या हुई तब से इस देश के अंदर यह एक चर्चा का विषय बना रहा कि षडयंत्रकारी कौन थे, हत्यारे कौन थे। हत्यारों को मद्रास हाई कोर्ट ने सजा दी मगर षडयंत्रकारी कौन थे, यह अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है।

आए दिन समाचार-पत्रों में तरह-तरह के नाम, तरह-तरह की आर्गेनाइजेशंस, देश के अंदर, देश के बाहर, यह छपते रहते हैं और एक वातावरण को दूषित करते रहते हैं कि यह हत्या के पीछे राज क्या था, साजिश क्या थी और तरह-तरह की अफवाहों को जन्म देते हैं। रिपोर्ट एक सबमिट हुई और दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। जैसा कि मेरे साथी गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, यह भी बड़ा गंभीर विषय है कि गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सबमिट होती है और वहां से सिस्टेमेटिकली उसको समाचार-पत्रों में लीक किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। पार्लियामेंट के सामने नहीं आती है, मगर समाचार-पत्रों में पहले जाती है। मेरा ख्याल है कि इस मामले में आपको सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि आखिर इस तरीके की बात क्यों की जा रही है। दूसरी बात जो मेरे मित्र ने उठाई कि विदेशी संस्थाएं और विदेशी व्यक्ति आज धन दे रहे हैं उनके लिए यह जो कातिल है, और जिनको कैपिटल पनिशमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने दी है, उनका किस तरीके से बचाव किया जाए। यह भी एक बहुत ही गंभीर विषय है और ऐसी-ऐसी आर्गेनाइजेशंस का नाम आ रहा है जो जाने-माने माफिया एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप्स, वर्ल्ड नोन जो हैं, उनके नाम इन समाचार-पत्रों में लिए जा रहे हैं। यदि उन ग्रुप्स ने, या उन आर्गेनाइजेशंस ने या उन व्यक्तियों ने अगर किसी व्यक्ति का नाम है, उनकी अगर एसोसिएशन है, तो यह राजीव गांधी की हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा षडयंत्र है। मैं चाहूंगा कि इसे बहुत ही गंभीरता से लें। सरकार पहले थी और आज दूसरी सरकार है। सरकार जो भी हो उसका उत्तरदायित्व होता है। यह एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री का मामला है, वे कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे ही, आज पूरे देश का उत्तरदायित्व बनता है कि हमें जानकारी हासिल हो सके, सभी देशवासी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे षडयंत्रकारी कौन थे और हत्यारे कौन थे।

मेरा सिर्फ यही आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए। इस पर बहस कराई जाए और बहस कराकर, यह जो एक अंधकार है उस अंधकार को साफ करके सच्चाई देश के सामने रखी जाए। धन्यवाद।

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, it is a very sensitive matter especially to us as the incident took place in our State. As far as the matter is concerned, our learned friend, Mr. Vayalar Ravi, and others have clearly mentioned that it is only through press reports that we are seeing the findings of the Final Report. Sir, I was shocked to see a newsitem in the *Indian Express* today captioned 'Jain backtracks on Tamils, says Karunanidhi should have been questoned' and 'Justice Jain recommends action against 21 additional suspects including former DMK Minister, Subbulakshmi Jagadeesan'. I would request the Government of India to place the Final Report of the Jain Commission before Parliament because the matter involves the Chief Minister of Tamil Nadu. In the final findings of the Report, it has been said and I quote: "Jain says that it is for this reason that he felt the Tamil Nadu Chief Minister, Shri M. Karunanidhi, should have been among the politicians who were questioned by

the Special Investigation Team which did the police investigations in the case. On many matters his interrogation was quite relevant. When Jain deals with his list of additional suspects in the assassination case (Volume IV) he prefers to refer to them as the supporters of chauvinist groups. There are 21 persons who figure in his fresh list of suspects." The newsitem further says and I quote: "Justice Jain has asked the Government to adopt such course of action as it may think fit against the list of suspects in the Rajiv Gandhi assassination case. Paving the way for additional charge-sheets being filed, Justice Jain explains that this would in no manner affect the original case against 41 accused persons. He says, "the trial by the designated court was only in respect of the 41 persons arraigned as accused by the SIT. It was not within the trial court to look beyond the 41 accused, so the question of exonerating the charge-sheet did not exist." There is a lot of controversy going on. The newsitem gives out a list of additional suspects both from Sri Lanka and India in which it has stated: "A former DMK Minister, Smt. Subbulakshmi Jagadeesan, had been questioned and released by the SIT. Justice Jain, however, says that her interrogation was laconic, sketchy and perfunctory. Subbulakshmi is alleged to have provided refuge to Santhan, an accused, in her farmhouse in Coimbatore after the assassination." The newsitem further states: "Further proof had come to the commission about the rear-base and facilitation being given to the LTTE-cadres during the DMK regime." Sir, Tamil Nadu is now being run by Mr. Karunanidhi. I would like to know whether the present Chief Minister of Tamil Nadu is directly involved in the assassination or not. Also, the Final Report has to be placed before Parliament at the earliest. Otherwise, it is only through Press reports that we come to know about the findings of the Jain Commission.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, today's *Indian Express* has carried out a newsitem that "Mr. Karunanidhi should also have been investigated" reported to have told by Justice Jain. Regarding Mrs. Subbulakshmi Jagadeesan he has mentioned that proper investigation has not taken place. From what he says, I fear that there is some motivation...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: He did not interrupt when you were speaking. So you should not interrupt when he is speaking.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: She had criticised the Centre and the State Government in a public meeting addressed by Shri Rajiv Gandhi for not doing anything to save the Tamils in Sri Lanka. She had said: "If the LTTE, in its present struggle against the Sri Lankan Government was defeated, the entire Tamil race in the island would be destroyed." This is what Jayalalitha said...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Do you want this Report to be tabled in the House or not? That is all.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: The hon. Member has questioned whether Mr. Karunanidhi has been involved in the murder or not. This is unwarranted, unnecessary,...(*Interruptions*) Once there was a question posed by the journalists to Ms. Jayalalitha. The question is: "Is not Mr. Karunanidhi helping the LTTE though it may not be to the same extent as MGR did." To this, the former Chief Minister, Ms. Jayalalitha said, "I see no evidence of it." Now a contrary stand has been taken. Ms. Jayalalitha herself had denied the DMK support to the LTTE. Now, they say...(*Interruptions*) Now, a contrary position has been taken. So it is to be placed on the Table of the House, we can have discussion on this. As far as DMK is concerned, we are not for any violence anywhere. We do not believe in that...(*Interruptions*)

SHRI R. MARGABANDU: But the Jain Commission had indicted you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: No. They have not indicted us (*Interruptions*) The Jain Commission has not indicted either DMK or...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let us not discuss the Jain Commission Report now. Let the Report be placed on the Table and then you can speak.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, today's *Indian Express* has clearly said that they have neither indicted DMK nor Mr. Kalaignar. Therefore, it is a false statement and it is an untrue statement (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Anyway, let the Report come. Both of you can speak then.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Mr. Chairman, Sir, first of all, I join my colleagues on this side in the sentiments that they have expressed in this House. It was indeed a great tragedy to lose a Prime Minister in this fashion. When originaly the notification in respect of the Jain Commission was issued, Sir, you might remember that there was a debate in the media as to why there should be a parallel inquiry when court proceedings are already going on. And the reasons why the inquiry continued was because it was felt that there might be a much larger conspiracy afoot to murder the Prime Minister. The Jain Commission took a long time, looked into several aspects of the matter and has now published the final report. Unfortunately, that report has not been placed before the House. But the issue that I would like to raise is the following.

If there are certain *prima facie* findings that the Jain Commission has rendered, which point out to a much larger conspiracy other than involving the 41 accused, then any further delay will only help the prospective accused to destroy the evidence that may be available. Therefore, it is in the fitness of things and imperative for justice to be done that immediate action is taken in two ways. First, it is not as if everything said in the Jain Commisison Report is the gospel truth. Ultimately, the Report is in the form of a recommendation that is placed before the Government and it is for the Government to apply its mind and find out to what extent certain findings of the Jain Commission are supported by tangible evidence. It is not fair for any Member of this House to start talking about this Chief Minister or that Chief Minister. Let the Government immediately apply its mind to the findings and place those findings before the House. That is number one. Secondly, let the Government immediately do it because any delay in this matter will only result in the destructon of evidence. And if that evidence is destroyed, the larger conspirators will never be brought to book. So, I support my learned friends and say, let the Report be placed before the House and let the Action Taken Report be placed before the House.

MR. CHAIRMAN: Now, there is one Special Mention regarding the postal strike. Would you like to take it up now or after Lunch?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: It is important, Sir. We should take it up now.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Yes, Sir. Let us take it up now.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, before you take up the postal strike, I want to say something on the Jain Commission Report.

MR. CHAIRMAN: That is over.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Only one minute, Sir.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I associate myself with the views expressed by my friend, Shri Suresh Pachouri, and others. You just now heard the Special mention made by Shri Malhotra. It is a very serious matter. We have lost two Prime Ministers

already. It is a very serious issue. The Jain Commission Report was submitted to the Government about three months back. It has still not seen the light of the day. We are being kept in the dark. Sir, you are the custodian of the House. We have seen the hon. Members referring to Press clippings today. We are not referring to the Jain Commission Report. How long will it continue like this?

How long will it continue like this? As per the Jain Commission Report, as reported in the Press, it is crystal clear that our intellligence machinery had failed. As per the Jain Commission Report submitted to the Government, there are so many conspirators and it has been proved. What action has been taken in this regard? We have been kept in darkness. I want to know whether the Government is waiting for some more murders to be committed. As a result of these militant activities, we have lost our Prime Ministers, Chief Ministers and thousands of people. I want to know whether it is not a serious matter which should be considered by this House. Sir, as you are the custodian of the House, you have got more responsibilities. One Minister is still present in the House even the Minister in-charge of Parliamentary Affairs was also present in the House. Kindly direct them to expedite the matter; otherwise, so many things will happen, and particularly the evidence will be destroyed. Hence my request is that this Report should be placed on the Table of House immediately.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I just like to add one thing. It is obligatory on the part of the Government and as per the Commission of Inquiries Act, 1956, they will have to place the Report of the Committee along with the Action Taken Report. We expected that the Government should have placed this Report—at least indicated that during this Session they would like to place the Report along with the Action Taken Report, whatever Action Taken Report has been prepared, whatever action they have taken. Therefore, I would like to have some response from the Government, they should indicate to us—some Cabinet Minister is sitting—by what time—because we know the schedule of the present Session—we are expected to have the Report placed on the Table of the House along with the Action Taken Report.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, there is no response from Minister ...(*Interruptions*)...

Postal Strike

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, we cannot but deeply deplore the attitude and policy of the Government with regard to the Postal strike which is continuing. It has entered the fourth day. A vital channel of communication in the country has totally collapsed. Much contrary to the boastful statements being made that nothing is wrong, something of the Postal system is still functioning, the facts are completely otherwise. The Postal Department has come to a standstill. Lakhs of Postal employees are on strike. Maybe, it has entered the fourth day and the Government appears to be silent. At least, the Parliament which is in Session is not being informed about the negotiation that is continuining. I thought, the House expected the hon. Minister looking after Communications, of course, it is an additional charge—will inform the House. What is happening to that? How long is this strike going to continue? Therefore, the whole policy appears to be devoid of any responsibility and extremely casual. The Prime Minister, only the other day, said that negotiations are going on. Sushmaji said in the other House that talks are going on, but how long will the talks go on?

Sir, the Tandon Committee Report was submitted to the Government much